सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त Public Finance and Private Finance:

1. सार्वजनिक वित्त:

सार्वजनिक वित्त केवल सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय की संरचना का अध्ययन करने के लिए ही नहीं है अपितु यह संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की चिंता के रूप में आर्थिक प्रणाली की समग्र गतिविधियो, रोजगार, कीमतों और विकास प्रक्रिया के स्तर पर सरकारी राजकोषीय संचालन के प्रभाव की एक पूरी चर्चा को भी शामिल करता है।

हम सार्वजनिक वित्त में सरकार की आय, व्यय और उसके प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओ का अध्ययन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियां, कंपनियां और राज्य कार्यालय शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जनता को सामाजिक लाभ प्रदान करना है।

1.1 निजी वित्त:

किसी भी निजी कंपनी या व्यक्ति के वित्त से संबंधित कारक को निजी वित्त कहा जाता है। एक निजी वित्त पूंजी निवेश के लिए धन प्रदान करने का एक तरीका है, जहां निजी कंपनियों को सार्वजनिक परियोजनाओं को पूरा करने और प्रबंधित करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। एक निजी वित्त के तहत, निजी कंपनिया, सरकार के बजाय खुद स्टॉक संभालती है । निजी क्षेत्र के व्यवसाय, कंपनियां और व्यक्तियो का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है।

1.2 **सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच संबंध Relationship between Public Finance and Private Finance):**

सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच पारस्परिक और पूरक संबंध है। इस सम्बन्ध मे कुछ महत्तपूर्ण दृष्टिकोण निम्न प्रकार हैं-

1. सार्वजनिक और निजी वित्त में आय और व्यय का समायोजन-

सरकार, व्यय बजट के अनुसार आय को समायोजित करती है। सरकार पहले खर्च के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, फिर उपकरणों के लिए आवश्यक मौद्रिक बजट प्राप्त करना होता है जबकि व्यक्तियों और निजी व्यवसायों सहित निजी क्षेत्र, आय या भविष्य के आय अनुमानों के अनुसार अपने खर्च को समायोजित करने का प्रयास करते हैं।

2. सार्वजनिक बनाम निजी वित्त में उधार लेना-

जब वित्तीय कमी उत्पन्न होती है तो सरकारे खुद से उधार ले सकती है या वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण मांगने के लिए लोगों के पास जा सकती है जबकि एक निजी वित्त मे एक व्यक्ति खुद से उधार नहीं ले सकता है।

3. सार्वजनिक बनाम निजी वित्त में मुद्रा स्वामित्व:

सरकारे मुद्रा से संबंधित सभी पहलुओं की प्रभारी है। इसमें आय निर्माण, वितरण और निगरानी शामिल है। निजी क्षेत्र में किसी को भी मुद्रा निर्गमन की अनुमति नहीं है, यह अवैध है और अधिकांश देश इसे पूंजी अपराध के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

4. वर्तमान आय बनाम भविष्य की आय :
सार्वजनिक क्षेत्र, भविष्य की योजना बनाने और दीर्घकालिक निर्णय लेने में अधिक शामिल होते है। सरकार ऐसे निर्णय लेती है जो लंबे समय तक लाभ देंगे। इस प्रकार के निर्णयो, निवेशों मे स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हो सकता है जबकि निजी उद्योग छोटे आमदनी वाली परियोजनाओं पर वित्तीय निर्णय लेते है।

5. सार्वजनिक और निजी वित्त में उद्देश्य का अंतर:
सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सामाजिक लाभ पैदा करना है। एक निजी उद्योग व्यक्तिगत लाभों को अधिकतम करना चाहता है।

6. व्यक्तियों से राजस्व, कर प्राप्त करने के लिए सरकारे बल का उपयोग कर सकती है। हालांकि निजी क्षेत्र के पास यह अधिकार नहीं होता है।

7. जानबूझकर परिवर्तन करने की क्षमता सार्वजनिक वित्त क्षेत्र में बहुत अधिक है। परिणामों को जाने बिना आय राशि पर भारी निर्णय लेने की क्षमता है। यह प्रभावी रूप से और जानबूझकर आय राशि को तुरंत बढ़ा या घटा सकता है। जबकि निजी व्यवसाय और व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले सकते हैं ।

8. अतिरिक्त आय या अधिशेष बजट निजी क्षेत्र में एक बड़ा गुण है, हालांकि यह सार्वजनिक वित्त में ऐसा नहीं है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल वित्तीय वर्ष के लिए ही जो आवश्यक हो उतना ही अधिशेष बजट रखे।